दैनिक भारत कि

तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

बीड (महाराष्ट्र) वर्ष-२ ला अंक-६७ वा गुरूवार ११ दिसंबर २०२५ RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 किमत : २ रूपये पन्ने - ४

विधानसभा अध्यक्ष का रामशास्त्री प्रभुणे वाला कठोर रूप'!

महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की कार्यशैली को लेकर विपक्ष लंबे समय से उन्हें पक्षपाती करार देता रहा है। विशेषज्ञ भी कई मौकों पर इन आरोपों में तथ्य होने की बात मानते हैं। मगर बुधवार को सदन में उनके भीतर का रामशास्त्री प्रभुणे जैसा निष्पक्ष और कठोर रूप' पहली बार स्पष्ट रूप से दिखाई दिया।

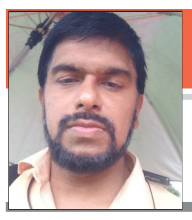

शीतकालीन अधिवेशन डायरी

- जमीर काझी

अल्पमत और कमजोर स्थिति में मौजूद विपक्ष द्वारा उठाए गए उचित मुद्दों पर उन्होंने मंत्रियों और सरकार को सख्त लहजे में फटकार लगाई। इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल-माफी की घोषणा होने के बावजूद उनसे टोल वसूली जारी रहने पर उन्होंने नाराजगी जताई और निर्देश दिया कि आठ दिनों के भीतर इस नीति का १००% पालन सुनिश्चित किया जाए तथा घोषणा के बाद हुई गलत वसूली की रकम वाहन मालिकों को वापस की जाए।

मुंबई की नगर निगम शालाओं के निजीकरण पर कांग्रेस विधायक अस्लम शेख द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा जब मुद्दे को धार्मिक रंग देने लगे, तो अध्यक्ष नार्वेकर ने उन्हें तुरंत रोक दिया और केवल विषय पर बोलने को कहा।

इसी तरह, राज्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के प्रस्ताव पर जोर दे रहे नाना पटोले को भी उन्होंने सदन के नियम विस्तार से समझाकर शांत किया।

शिवसेना और राष्ट्रवादी में विभाजन तथा बागी विधायकों की पात्रता पर निर्णय में विलंब के चलते नार्वेकर अक्सर विपक्ष के निशाने पर रहते हैं। आरोप यह भी रहता है कि वे विपक्ष को बोलने का पर्याप्त समय नहीं देते। लेकिन अधिवेशन के तीसरे दिन की प्रश्नोत्तर अवधि में इसका बिल्कुल उलटा दृश्य देखने को मिला-अध्यक्ष ने विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सरकार को निर्णायक और स्पष्ट निर्देश दिए।

ठाकरे गुट के विधायक हारून खान ने वर्सोवा स्थित क्रिस्टल पॉइंट मॉल में बार-बार होने वाले अवैध निर्माण की शिकायत रखी। मंत्री माधुरी मिसाळ ने बताया कि दंड वसूल किया गया है, पर जब यह स्पष्ट हुआ कि अवैध निर्माण दंड भरकर नियमित किए जा रहे हैं और फिर दोबारा किए जा रहे हैं, तो अध्यक्ष ने एमआरटीपी अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया।

मुंबई नगर निगम चुनावों से पहले मालवणी क्षेत्र में कथित धार्मिक ध्रुवीकरण और बीएमसी की टाउनशिप स्कूल को पीपीपी मॉडल पर सौंपकर अपात्र शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने का मुद्दा विपक्ष ने उठाया। मंत्री मिसाळ पर्याप्त जानकारी देने में विफल रहीं। लोढ़ा ने फिर धार्मिक संदर्भ जोड़ने की कोशिश की, जिसे अध्यक्ष ने रोक दिया। बाद में शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने उत्तर दिया, लेकिन वह भी संतोषजनक न होने पर अध्यक्ष ने गलत जानकारी देने पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति २०२५' के तहत प्रमुख महामार्गों पर इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल-माफी लागू होने का दावा सरकार ने किया था। लेकिन ऑनलाइन टोल-कटौती अब भी हो रही है, यह तथ्य वरुण सरदेसाई ने प्रमाण सहित सदन के समक्ष रखा। इस पर अध्यक्ष ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई और आठ दिनों में नीति का कठोरता से पालन कराने तथा चुकी हुई वसूली तुरंत लौटाने का आदेश दिया।

राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा गलत जानकारी दिए जाने के आरोप में उन्हें पद से हटाने के मुद्दे पर नाना पटोले जोर दे रहे थे, पर अध्यक्ष ने संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देकर स्पष्ट किया कि यह प्रस्ताव नियमों के अनुरूप नहीं है।

आज की प्रश्नोत्तर अवधि में अध्यक्ष की निष्पक्ष और दृढ़ भूमिका देखकर विपक्ष के चेहरों पर स्पष्ट रूप से संतोष दिखाई दिया।

जालंधर वक्फट्रिब्यूनल ने UMEED पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए दो महीने की बढ़ोतरी दी

जालंधर (पंजाब),

तामीर संवाददाता

१० दिसंबर २०२५: पंजाब के जालंधर वक्फ ट्रिब्यूनल ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम २०२५ के तहत UMEED (Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development) पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य पंजीकरण की समय सीमा में दो महीने की बढ़ोतरी का महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। यह फैसला पंजाब वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई के बाद लिया गया, जिसमें बोर्ड ने तकनीकी खराबियों, दस्तावेजों की अनुपलब्धता और प्रशासनिक बाधाओं का हवाला दिया। नई अंतिम तिथि अब ६ फरवरी २०२६ हो गई है, जो मुतवल्लियों (वक्फ संपत्तियों के प्रबंधकों) को राहत प्रदान करेगी।

पृष्ठभूमि और महत्व

केंद्र सरकार ने ६ जून २०२५ को वक्फ (संशोधन) अधिनियम २०२५ के अंतर्गत णचएएऊपोर्टल लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य देशभर की लगभग ९ लाख वक्फ संपत्तियों का डिजिटल पंजीकरण, जियो-टैगिंग और पारदर्शी निगरानी सुनिश्चित करना है। अधिनियम की धारा ३इ(१) के अनुसार, सभी पंजीकृत वक्फ संपत्तियों का विवरण ६ महीने के भीतर (यानी ६ दिसंबर २०२५ तक) पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य था। हालांकि, पोर्टल की तकनीकी समस्याओं, दस्तावेजों की पुष्टि में देरी और अन्य चुनौतियों के कारण कई मुतवल्लियों और वक्फ बोर्डों ने समय सीमा पूरी करने में असफलता दिखाई।

इस स्थिति पर प्रतिक्रिया में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) और अन्य मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। १ दिसंबर २०२५ को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने राष्ट्रीय स्तर पर समय सीमा बढ़ाने की सामान्य याचिका खारिज कर दी। अदालत ने धारा ३इ की उप-धारा का संदर्भ देते हुए कहा कि ट्रिब्यूनल मुतवल्ली की याचिका पर उचित कारणों से अतिरिक्त ६ महीने तक बढ़ोतरी दे सकता है। अदालत ने जोर दिया: ट्रिब्यूनल ही उचित मंच है, जहां केस-दर-केस आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। इसके बाद मुतवल्लियों ने विभिन्न राज्यों के वक्फ ट्रिब्यूनलों से संपर्क किया।

जालंधर ट्रिब्यूनल का आदेश: विस्तृत विवरण

जालंधर वक्फ ट्रिब्यूनल ने ६ दिसंबर २०२५ को पंजाब वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई की और दो महीने की बढ़ोतरी मंजूर कर ली। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में पोर्टल की तकनीकी खराबियों, दस्तावेजों की सत्यापन में देरी और बोर्ड द्वारा अब तक की प्रगति रिपोर्टों का उल्लेख किया। आदेश में कहा गया: वक्फ बोर्ड ने ईमेल और अन्य प्रमाण प्रस्तुत किए जो पंजीकरण में बाधाओं की पहचान करते हैं। यह बढ़ोतरी केवल उन संपत्तियों के लिए है जो पहले से पंजीकृत हैं लेकिन जिनका विवरण अपलोड नहीं हो सका।

ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि बढ़ोतरी की अवधि के दौरान मुतवल्लियों को तत्काल अपलोडिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी, अन्यथा ५०,००० रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह निर्णय गुजरात और मध्य प्रदेश के वक्फ ट्रिब्यूनलों के हालिया आदेशों पर आधारित है, जहां ६ महीने की बढ़ोतरी दी गई थी (जून २०२६ तक)। पंजाब में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन सीधे बोर्ड द्वारा किया जाता है, न कि मुतवल्लियों द्वारा, जिससे प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल रही। ४ दिसंबर २०२५ तक पंजाब में लगभग ८०% वक्फ संपत्तियां पंजीकृत हो चुकी थीं, जो अन्य राज्यों से बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है।

ट्रिब्यूनल के चेयरमैन ने कहा कि यह बढ़ोतरी वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और डिजिटलीकरण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है, लेकिन मुतवल्लियों को सलाह दी जाती है कि वे स्थानीय वक्फ बोर्ड या ट्रिब्यूनल से तुरंत संपर्क करें। जालंधर ट्रिब्यूनल ने अब तक २०० से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई की है, जिनमें से अधिकांश को वैयक्तिक आधार पर राहत दी गई।

पंजाब वक्फ बोर्ड का प्रदर्शन और चुनौतियां

पंजाब वक्फ बोर्ड के पास लगभग १०,००० से अधिक वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान और अन्य धार्मिक संस्थान शामिल हैं। बोर्ड ने पंजीकरण प्रक्रिया को तेज करने के लिए 'वक्फ एस्टेट' पंजीकरण को प्राथमिकता दी, जिससे मुतवल्लियों का बोझ कम हुआ। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी और पुराने दस्तावेजों की डिजिटलीकरण में देरी प्रमुख बाधाएं रहीं। बोर्ड के सीईओ ने बताया कि बढ़ोतरी के बाद वे विशेष वर्कशॉप आयोजित करेंगे ताकि शेष २०% संपत्तियों का पंजीकरण फरवरी तक पूरा हो सके।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ५ दिसंबर २०२५ को कहा कि दिसंबर २०२५ से अगले तीन महीनों तक देरी से पंजीकरण पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा, लेकिन यह ट्रिब्यूनल की बढ़ोतरी का विकल्प नहीं है। अब तक णचएएऊ पोर्टल पर ५.१७ लाख से अधिक संपत्तियां पंजीकृत हो चुकी हैं, जिनमें पंजाब का योगदान उल्लेखनीय है।

विशेषज्ञों और प्रभावित पक्षों की प्रतिक्रिया

वकील और वक्फ विशेषज्ञों का मानना है कि यह बढ़ोतरी एक अस्थायी राहत है, लेकिन बड़े पैमाने पर पंजीकरण के लिए और सहायता की जरूरत है। -खचझडइ के महासचिव मौलाना फजलुर रहमान ने अपील की: जल्द से जल्द पंजीकरण पूरा करें, वरना संपत्तियों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जमीयत उलेमा महाराष्ट्र के अध्यक्ष मौलाना हलीमुल्लाह कासमी ने राज्य स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित करने की घोषणा की। जालंधर के स्थानीय मुतवल्लियों ने ट्रिब्यूनल के फैसले का स्वागत किया, लेकिन चिंता जताई कि दो महीने पर्याप्त होंगे या नहीं। यह कदम वक्फ संपत्तियों की रक्षा और डिजिटलीकरण को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। मुतवल्लियों को सलाह दी जाती है कि वे तुरंत जालंधर वक्फ ट्रिब्यूनल या पंजाब वक्फ बोर्ड से संपर्क करें।

तेंदुए के भेस में विधायक विधानभवन पहुंचे!

तुरंत उपाययोजनाओं की मांग, राज्य मे १० हजार तेंदुए।

जमीर काझी (फोटो)

राज्य में तेंदुओं के मानव बस्तियों पर हमले दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अब केवल पश्चिम महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र और विदर्भ में भी तेंदुओं के आने से नागरिकों में दहशत का माहौल है। हिवाळी अधिवेशन चल रहा है और नागपुर में भी बुधवार सुबह तेंदुआ मानव बस्ती में घुस आया और उत्पात मचाया। इस गंभीर मुद्दे पर सरकार ठोस कदम उठाए, इसके लिए जगह-जगह जनआंदोलन खड़े हो रहे हैं।

सरकार का ध्यान इस ओर खींचने के लिए महायुती के एक विधायक ने बुधवार को विधानभवन में पूरी तरह तेंदुए का वेश और मास्क पहनकर प्रवेश किया। उनका यह अवतार आज पूरे दिन चर्चा का विषय बना रहा।

शिवसेना (शिंदे गुट) के मंचर विधायक श्री शरद सोनवणे ने खुद को तेंदुआ' बनाकर तत्काल उपाययोजना लागू करने की मांग की।

तेंदुओं के हमलों में कई मासूम बच्चों को जान गंवानी पड़ी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। पश्चिम महाराष्ट्र विशेषकर जुन्नर तालुका, अहमदनगर, सोलापूर, नासिक, धुले, मुंबई उपनगर, मराठवाड़ा और विदर्भ के नागपुर क्षेत्र में तेंदुआ-बाघ की दहशत फैली हुई है। हमले बढ़ने के बावजूद रोज की कार्रवाई के अलावा कोई ठोस उपाय नहीं हो रहे, इसलिए जुन्नर के विधायक शरद सोनवणे तेंदुए के वेश में ही विधानसभा पहुंचे और हिवाळी सत्र में इस समस्या को गंभीरता से देखने की अपील की। उनके इस लुक और मुद्दे की नागपुर में ज़ोरदार चर्चा हो रही है।

शरद सोनवणे ने कहा, नागपुर की सीमा पर भी तेंदुआ पहुंच चुका है। राज्य में ९-१० हजार तेंदुए हैं। सिर्फ जुन्नर तालुका में पिछले तीन महीनों में ५५ लोग तेंदुओं के हमले में मारे गए हैं। उन्हें पकड़ने की बजाय सरकार महिलाओं-किसानों-बच्चों को लोहे की पट्टी वाला कंठा पहनने की सलाह दे रही है। हमारे बच्चे आंगन में नहीं, सड़क पर नहीं दिखते, स्कूल नहीं जा रहे। घर के चारों ओर करंट वाली तार लगाकर हम अब कैद होने को मजबूर हैं। ऐसे कितने ही उपाय करके क्या हासिल होगा? इसका स्थायी हल निकालो।

रेस्क्यू ऑपरेशन चलाओ

उन्होंने मांग की कि राज्य में तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाए। आने वाले तीन महीनों में कम से कम दो हजार तेंदुओं की क्षमता वाले रेस्क्यू सेंटर बनाए जाएं। नर-मादी तेंदुओं को अलग-अलग रखा जाए ताकि नसबंदी का मुद्दा अपने आप खत्म हो जाए। इस हिवाळी सत्र के खत्म होने से पहले जुन्नर तालुका में दो और अहमदनगर में एक रेस्क्यू सेंटर तुरंत शुरू किया जाए। तेंदुओं पर माइक्रो-चिपिंग भी जरूरी है।

राज्य आपदा घोषित करो

श्री सोनवणे ने कहा, बकरियां छोड़ने से कुछ नहीं होगा, वे जंगल में चली जाएंगी, लेकिन तेंदुए तो अब गन्ने के खेतों और हमारे घरों के पास आ गए हैं। मुंबई में एसी कमरों में बैठे सचिवों को गांव की स्थिति नहीं पता। तीन-छह महीने के बच्चों की सुरक्षा का सवाल पैदा हो गया है। तेंदुए अब सिर्फ रात में नहीं, दिन में भी महिलाओं-पुरुषों पर हमला कर रहे हैं। इसलिए तेंदुओं के हमलों को राज्य आपदा' घोषित किया जाए।

मुख्यमंत्री को तुरंत इसकी घोषणा करनी चाहिए। आगे से एक भी किसान या उसके बच्चे का बलि हमें मंजूर नहीं।

उन्होंने आगे कहा, तेंदुआ शेड्यूल-१ का जानवर नहीं, शेड्यूल-२ का है, उसे वहीं रखें। मृतक परिवार को २५ लाख रुपये देने से बेहतर है कि जिंदगी बचाई जाए। जगह प्रचुर है। ९० दिन में रेस्क्यू सेंटर तैयार करें और आगे एक भी तेंदुआ खुले में न घूमे, ऐसी व्यवस्था करें।

झेडपी-महापालिका चुनाव में महायुती एकजुट होकर लड़ेगी-चद्रशेखर बावनकुळे

नागपुर : जमीर काजी

जिला परिषद और महानगर पालिका चुनावों में महायुती पूरी एकजुट रहेगी। हमारा लक्ष्य ५१ प्रतिशत से अधिक वोट हासिल करके विजय प्राप्त करना है और ये सभी चुनाव महायुती एक साथ ही लड़ेगी। यह महत्वपूर्ण घोषणा प्रदेश के राजस्व मंत्री तथा स्थानीय स्वराज्य संस्था चुनाव के भाजपा प्रभारी चंद्रशेखर बावनकुळे ने की।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण और चंद्रशेखर बावनकुळे की एक बैठक हुई। पत्रकारों से बातचीत में बावनकुळे ने कहा, जिला स्तर के सभी नेताओं को स्थानीय स्तर पर महायुती को मजबूत करने के निर्देश दे दिए गए हैं। स्थानीय स्तर पर ५ से १० प्रतिशत सीटों पर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन ऐसी जगहों पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे स्वयं बैठकर अंतिम फैसला लेंगे।

मुंबई के लिए चार-प्लस-चार का फॉर्मूला

मुंबई महानगर पालिका के लिए भी महायुती पूरी तरह तैयार है। शिवसेना ने ९० से १०० सीटों की मांग की है, लेकिन सीट बंटवारा तकनीकी पहलुओं की जांच के बाद ही तय होगा। इसके लिए भाजपा और शिवसेना के चार-चार वरिष्ठ पदाधिकारी तथा महायुती के प्रतिनिधियों की एक समन्वय समिति बनाई गई है जो एक साथ बैठकर चर्चा करेगी। जहां मतभेद होंगे, वहां शीर्ष नेता फैसला करेंगे। मुंबई के महापौर पद का निर्णय देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार मिलकर लेंगे।

पिछले स्थानीय निकाय चुनावों में कुछ जगहों पर कार्यकर्ताओं में मतभेद हुए थे, लेकिन अब वे पूरी तरह दूर हो चुके हैं। हमारे बीच कोई मनभेद नहीं था, सिर्फ चुनावी मतभेद थे, ऐसा बावनकुळे ने स्पष्ट किया।

विदर्भ के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध

अलग विदर्भ के मुद्दे और विकास पर बोलते हुए बावनकुळे ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, २०१४ में देवेंद्र फडणवीस की सरकार आने के बाद विदर्भ का तेजी से विकास हुआ है। छोटे राज्य भी विकसित हो सकते हैं, इस पर भाजपा का पूर्ण विश्वास है और विदर्भ को पूरा न्याय देने की हमारी कोशिश जारी है। विदर्भ में सबसे अधिक जंगल हैं, इसलिए वन विभाग का मुख्यालय मुंबई नहीं ले जाया जाएगा।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

सोलापुर मनपा ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों को तीन करोड़ और शिक्षकों को एक करोड़ का भुगतान होगा

सोलापुर (इकबाल बागबान): सोलापुर महानगरपालिका ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारियों के बकाया राशि के रूप में तीन करोड़ रुपये तथा प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के सेवारत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की बकाया राशि के तौर पर एक करोड़ रुपये तुरंत देने का फैसला मनपा आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे ने किया।

यह घोषणा आयुक्त ने वर्कर्स फेडरेशन के अध्यक्ष एवं पूर्व महापौर एडवोकेट यू. एन. बेरिया के नेतृत्व में तथा दोनों संगठनों के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में की।

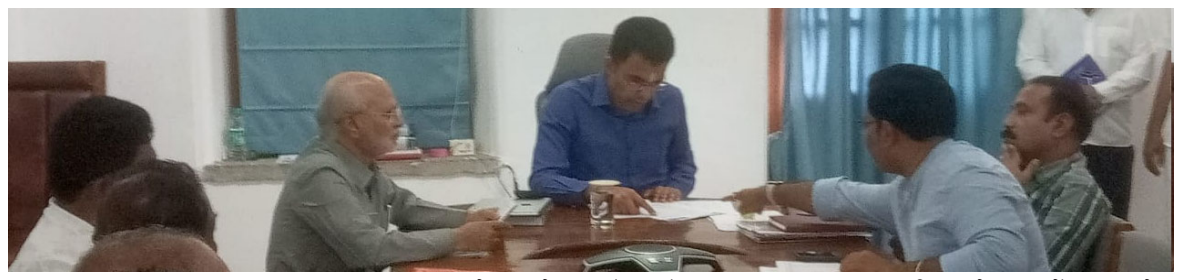

बैठक के निर्णय अनुसार:

ट्रांसपोर्ट विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया के लिए बजट से तीन करोड़ रुपये का फंड तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा।

प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के शिक्षकों एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की तीसरी किस्त के रूप में एक करोड़ रुपये फौरी तौर पर वितरित किए जाएंगे।

वर्तमान में सेवारत शिक्षकों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सैलरी-पेंशन हर महीने की १० तारीख से पहले सरकारी नियमों के अनुसार जमा करने के स्पष्ट निर्देश आयुक्त ने दिए।

इन ठोस फैसलों से शिक्षकों, कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों में खुशी और संतोष का माहौल है।

बैठक में ट्रांसपोर्ट विभाग के एन. एस. स्वामी, छगन बनसोडे, शिवानंद अजनालकर, नागेश महतरे, अब्दुल रज्जाक मकमदार, अनिल बागले, फजल शेख, इमरान पठान, नागेश गोसावी, कुद्दूस शेख, रफीक खान, फरकान पांगल, मदसर पिरजादे, फैयाज शेख, अरकल, नईम नाईकवाडी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। योग्यता के अनुसार नौकरी का अवसर आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे ने ट्रांसपोर्ट विभाग के ५० प्रतिशत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को, जो स्वास्थ्य एवं योग्यता की दृष्टि से फिट हैं, पुनः नौकरी देने का फैसला किया है। साथ ही ट्रांसपोर्ट विभाग के लिए जल्द ही उच्च शिक्षित एवं तकनीकी ज्ञान रखने वाले ट्रांसपोर्ट मैनेजर की नियुक्ति करने तथा नई बसें आने पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तुरंत वृद्धि करने का आश्वासन भी दिया है।

संक्षिप्त

एक लड़ाई माती के लिए: कपास-सोयाबीन उत्पादक किसान जनआंदोलन की तैयारी में

बीड (रिपोर्टर): गन्ने के भाव के लिए हुए राज्यव्यापी आंदोलन के बाद अब बीड जिले के कपास और सोयाबीन उत्पादक किसान बड़े जनआंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। समर्थन मूल्य न मिलने, उत्पादन लागत से कम बाजार भाव और लगातार नुकसान से किसानों में भारी आक्रोश है।

पारगाव जप्ती से शुरू हुआ आंदोलन अब पूरे जिले में फैल रहा है। नांदुर, पाली, अंथरवन, नाळवंडी, चौसाळा आदि गांवों में सैकड़ों किसानों की बैठकों का सिलसिला चल रहा है। हर बैठक में भाव बढ़ाने, समर्थन मूल्य, तत्काल आर्थिक मदद और फसल बीमा दावों जैसे मुद्दों पर गर्मागर्म चर्चा हो रही है।

बलभीम महाविद्यालय परिसर में कचरे के ढेर, जनस्वास्थ्य खतरे में

बीड (रिपोर्टर): शहर के बलभीम महाविद्यालय परिसर में मुख्य सड़क किनारे कचरे के बड़े-बड़े ढेर लगे हैं। बदबू से पूरे इलाके में दुर्गंध फैली है। रोजाना आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं को भारी परेशानी हो रही है। कई छात्र नाक पर रुमाल बांधकर चल रहे हैं।

बारिश के मौसम में हालात और गंभीर हो सकते हैं। कचरे से मच्छर-मक्खियां बढ़ गई हैं, जिससे डेंगू-मलेरिया और त्वचा-श्वास संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। छात्रों का आरोप है कि नगरपालिका की लापरवाही से यह स्थिति बनी है। उन्होंने तुरंत सफाई की मांग की है, वरना आंदोलन की चेतावनी दी है।

सोमवार या मंगलवार को जिला परिषद चुनाव की घोषणा संभव?

मुंबई: एक तरफ मुंबई महापालिका की मतदाता सूची में गड़बड़ी, दूसरी तरफ जिला परिषद-पंचायत समिति में ५०% से अधिक आरक्षण की सीमा पार होने से चुनाव होंगे या नहीं, इस पर चर्चा चल रही थी। अब सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग न्यायालय के आदेश के बाद चुनाव कराने की तैयारी में है।

आने वाले सोमवार या मंगलवार को चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिला परिषद, पंचायत समिति और महापालिका चुनावों की घोषणा कर सकता है। मुंबई की अंतिम मतदाता सूची के लिए ५ दिन की मोहलत बढ़ाई गई है। यह भी संभव है कि जिला परिषद-पंचायत समिति और महापालिका चुनाव एक साथ या चरणबद्ध तरीके से हों।

डोईठाण-आष्टी रास्ते पर तीन तेंदुओं का नाइट वॉक', दहशत

कड़ा (रिपोर्टर): आष्टी तालुका के किन्ही गांव के पास मुख्य सड़क पर एक साथ तीन तेंदुए दिखाई देने से इलाके में दहशत फैल गई है। एक यात्री ने साहस दिखाते हुए इसका वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

अक्टूबर में इसी इलाके में तेंदुए ने एक किसान राजेंद्र गोल्हार (३६) की जान ले ली थी। उस घटना की याद अभी ताजा है। ग्रामीणों ने रात में घर से बाहर न निकलने और वन विभाग से तेंदुओं को पकड़ने की मांग की है।

घरकुल योजना: सेल्फ सर्वे की जांच के लिए गांव-गांव अधिकारियों की नियुक्ति

बीड (रिपोर्टर): प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) फेज-२ के तहत हुए सेल्फ सर्वे की जांच के लिए जिला प्रशासन ने हर गांव के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किए हैं। ये अधिकारी गांव-गांव जाकर जांच करेंगे।

जिन पात्र परिवारों को अब तक घर नहीं मिला, उन्हें लाभ देने के लिए सेल्फ सर्वे कराया गया था। चौसाळा, पिंपळवाडी, लिंबागणेश, पालवण, राजुरी नवगण आदि कुल १७५ गांवों में यह जांच होगी।

लाडकी बहिन योजना किसी भी हालत में बंद नहीं होगी-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

नागपुर (रिपोर्टर): लाडकी बहिन योजना सरकार की जनकल्याणकारी और लोकप्रिय योजना है, इसे किसी भी स्थिति में बंद नहीं किया जाएगा। योजना शुरू करते समय हमने सकारात्मक सोच के साथ फैसला लिया था। यह बात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण सूचना के जवाब में कही।

विधायक सुनील प्रभु, जयंत पाटील, नानाभाऊ पटोले और हारून शेख ने योजना को लेकर सवाल उठाए थे। शिंदे ने कहा कि आचार संहिता के दौरान भी लाभार्थियों को कोई दिक्कत न हो, इसलिए पहले से ही पैसा उपलब्ध कराया गया था। बहनों ने सरकार पर भरोसा जताते हुए भारी जनादेश दिया है। इसलिए योजना को कम या बंद करने का सवाल ही नहीं उठता, बल्कि हमने जो-जो घोषणाएं की हैं, उन्हें समय पर पूरा किया जाएगा।

योजना के लिए कुल २ करोड़ ६३ लाख ८३ हजार ५८९ आवेदन आए थे, जिनमें से २ करोड़ ४३ लाख ८२ हजार ९३६ को पात्र माना गया। ई-केवायसी प्रक्रिया में अब तक १ करोड़ ७४ लाख से अधिक महिलाओं ने अपना प्रमाणीकरण पूरा कर लिया है। बाकी के लिए ३१ दिसंबर अंतिम तारीख है। गलत लाभ लेने वाले करीब ८ हजार सरकारी कर्मचारियों से राशि की वसूली चल रही है, जो अगले दो महीनों में पूरी हो जाएगी।

पिंपळवाडी सबस्टेशन को ५ एमव्ही का नया ट्रांसफार्मर मंजूर-मस्के

बीड (रिपोर्टर): बीड तालुका के पिंपळवाडी सबस्टेशन के लिए ५ एमव्ही क्षमता का नया ट्रांसफार्मर मंजूर हो गया है। जल्द ही यह काम पूरा हो जाएगा, जिससे सबस्टेशन की क्षमता दोगुनी हो जाएगी। यह जानकारी राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) के जिला अध्यक्ष राजेंद्र मस्के ने दी।

सूर्याचीवाडी, भाळवणी, देवर्याचीवाडी आदि क्षेत्रों में अभी दो दिन छोड़कर बिजली दी जा रही थी, अब इसे रद्द कर एक ही दिन में दो चरणों में दिन के समय बिजली दी जाएगी। मस्के ने आज महावितरण के अधीक्षक अभियंता से मुलाकात कर किसानों की मांग रखी, जिसे मंजूरी मिल गई। इससे क्षेत्र के किसानों को दिन में कृषि पंप चलाने में सुविधा होगी।

महाराष्ट्र को पंप स्टोरेज हब बनाने का लक्ष्य-मुख्यमंत्री

नागपुर , जमीर काजी

महाराष्ट्र ने पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स में अब तक ७६,११५ मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता हासिल कर ली है। राज्य को देश का पंप स्टोरेज हब बनाने का लक्ष्य है। हाल ही में हुए समझौता ज्ञापनों से ५,८०० मेगावाट अतिरिक्त क्षमता जुड़ेगी। इन प्रोजेक्ट्स में २३,८०० करोड़ रुपये का निवेश और ११,५०० नौकरियों का सृजन होगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी।

मुख्यमंत्री की उपस्थिति में पश्चिम घाट पंप स्टोरेज, कोयना स्टेज-६ और सरोवर पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए जलसंपदा विभाग तथा गव्ध नियो एनर्जी, महाजेंको रिन्यूएबल एनर्जी और न्यू एशियन इंफ्रा डेवलपमेंट प्रा. लि. के साथ कुल ५४ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए।

ओबीसी विद्यार्थियों की शैक्षणिक योजनाओं को और गति देंगे - मंत्री अतुल सावे

नागपुर

ओबीसी और अन्य वंचित वर्गों के छात्रों की शैक्षणिक उन्नति के लिए राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है और इन्हें और तेज किया जाएगा। यह बात अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे ने विधान परिषद में कही।

विदेशी शिक्षा छात्रवृत्ति योजना २०१७ में केवल १० छात्रों तक सीमित थी, अब इसे बढ़ाकर ७५ किया गया है और आगे और बढ़ाया जाएगा। म्हाडा-सीडको के मकानों में आरक्षण, छात्रावासों के लिए भवन किराए पर लेना, २० लाख तक विदेशी शिक्षा ऋण और १० लाख तक देशी उच्च शिक्षा ऋण जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया गया है।

विकास सेवा संस्थाएं सक्षम होना जरूरी - सहकार मंत्री

नागपुर

किसानों को आसानी से कर्ज मिले, इसलिए विकास सेवा संस्थाओं का सक्षम होना आवश्यक है। एक राजस्व गांव में एक से अधिक संस्था नहीं खोली जाएगी। यदि मौजूदा संस्था सक्षम है तो नई संस्था खोलने की अनुमति दी जाएगी। यह बात सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील ने विधान परिषद में कही।

अहमदनगर के जामखेड तालुका में प्रस्तावित पुण्यश्लोक विविध कार्यकारी सहकारी विकास सेवा संस्था को जिला सहकारी बैंक की शाखा में खाता खोलने और कर्ज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाएंगे।

संगमनेर में कन्फर्मेशन डीड के लिए तीन दिवसीय विशेष शिविर - महसूल मंत्री

नागपुर

अहमदनगर जिले के संगमनेर के इंदिरानगर क्षेत्र में कन्फर्मेशन डीड नोंदणी पूरी करने के लिए अगले तीन दिन विशेष शिविर लगाया जाएगा। साथ ही, यदि सहायक दुय्यम निबंधक ने जानबूझकर टालमटोल की तो उनकी बदली की जाएगी। यह घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विधान परिषद में की।

मामले की जांच निबंधन महानिरीक्षक से कराई जाएगी और रिपोर्ट आने पर उचित कार्रवाई होगी।

नंदुरबार माध्यमिक शिक्षा अधिकारी निलंबित, जांच के आदेश - शिक्षा मंत्री

नागपुर

नंदुरबार के जिला माध्यमिक शिक्षा अधिकारी पर २०२० में पुणे में उपसंचालक रहते हुए फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकार को धोखा देने का मामला दर्ज है। उनकी वर्तमान शिकायतों को देखते हुए उन्हें तत्काल निलंबित कर १५ दिन में जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। यह जानकारी शालेय शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने विधान परिषद में दी।

शालार्थ आईडी मामले में भी विशेष जांच दल गठित है और तीन महीने की मोहलत बढ़ाई गई है।

पिंपरी-चिंचवड़ मालमत्ता सर्वेक्षण में अनियमितता; जांच के बाद ही बाकी भुगतान - उद्योग मंत्री उदय सामंत

नागपुर

पिंपरी-चिंचवड़ महापालिका द्वारा मालमत्ता सर्वेक्षण के लिए नियुक्त कंपनी स्थापत्य कंसल्टेंसी इंडिया प्रा. लि. के काम में अनियमितता की जांच पूरी होने के बाद ही बाकी बिल का भुगतान किया जाएगा। यह बात उद्योग मंत्री उदय सामंत ने विधान परिषद में कही।

५.८० लाख संपत्तियों के सर्वे के लिए ४७.९५ करोड़ का ठेका दिया गया था, लेकिन ३.७० लाख नई संपत्तियां मिलने पर अतिरिक्त २९ करोड़ मंजूर हुए, जिनमें से अभी सिर्फ १२ करोड़ ही दिए गए हैं।

आश्रमशाला शिक्षकों को शाला संहिता के अनुसार वेतनमान जल्द - सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट

नागपुर

स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही आश्रमशालाओं के शिक्षकों को शाला संहिता के अनुसार वेतनमान देने के प्रस्ताव पर सरकार सकारात्मक है। प्रस्ताव अंतिम चरण में है और जल्द ही वित्त विभाग को भेजकर मंत्रिमंडल में रखा जाएगा। यह जानकारी सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने विधान परिषद में दी।

मुंबई ट्रैफिक प्लानिंग और ई-चालान के लिए अध्ययन समूह गठित होगा - मुख्यमंत्री

नागपुर

मुंबई और आसपास बढ़ती वाहन संख्या को देखते हुए ट्रैफिक मैनेजमेंट और ई-चालान के लिए आधुनिक तकनीक जरूरी है। विभिन्न राज्यों व देशों की अच्छी प्रथाओं का अध्ययन करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में अध्ययन समूह बनाया जाएगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में की। ट्रैफिक पुलिस को कैमरा देने पर भी विचार चल रहा है।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com